भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 526

उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2026 (गुरूवार)

1 श्रावण, 1948 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) के कार्यान्यवन की प्रगति

526# **श्री अमर पाल मौर्यः**

श्री रामराव सखाराम वाडकुटेः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) के अंतर्गत अनुमोदित, पूर्ण तथा कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं सहित इसके अंतर्गत हुई प्रगति का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित एवं जारी की गई धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या पीएम-डिवाइन के अंतर्गत कोई नई परियोनजाएँ स्वीकृत की गई हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन और परिणाम-आधारित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): अक्तूबर 2022 में इस स्कीम की शुरुआत से लेकर दिनांक 30.06.2026 तक, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन) के तहत कुल 53 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है, जिनकी कुल लागत 6501.79 करोड़ रुपये है। इनमें से 344.01 करोड़ रुपये की लागत वाली 4 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान इस स्कीम के तहत आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आवंटन	उपयोग
1	2025-26	1454.22 (आरई)	1422.96
2	2026-27	2300 (बीई)	778.91 (30.06.2026 तक जारी)

(घ) मंत्रालय राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकों, जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प्ड फोटोग्राफों का उपयोग करके डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी; मंत्रालय/उत्तर पूर्वी परिषद/फील्ड तकनीकी सहायता इकाइयों (एफटीएसयू)/परियोजना गुणवत्ता प्रबोधन (पीक्यूएम)/तृतीय पक्ष तकनीकी निरीक्षण (टीपीटीआई) एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षण और स्थल दौरा आदि के माध्यम से पीएम-डिवाइन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

इन समीक्षाओं के माध्यम से, कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं, यदि कोई हो, की पहचान की जाती है और राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना निगरानी को सुदृढ़ करने, निष्पादन में तेजी लाने, धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने और कार्यान्वयन कार्यक्रम का पालन करने की सलाह दी जाती है।

****

अनुबंध

"उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) के कार्यान्यवन की प्रगति" विषय पर राज्य सभा में दिनांक 23.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 526 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(30.06.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	**राज्य**	**स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या**	**परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत (राशि करोड़ रुपये में)**	**30.06.2026 तक जारी कुल धनराशि (राशि करोड़ रुपये में)**	**पूरी हो चुकी परियोजनाओं की संख्या**
1	अरुणाचल प्रदेश	6	832.80	214.31	-
2	असम	4	1402.50	745.53	-
3	मणिपुर	7	561.00	279.78	-
4	मेघालय	7	773.90	339.99	-
5	मिजोरम	2	595.24	236.29	-
6	नागालैंड	7	552.83	307.12	-
7	सिक्किम	5	561.11	437.99	3
8	त्रिपुरा	6	619.18	310.43	-
9	केंद्रीय एजेंसी	9	603.23	214.71	1
	कुल	**53**	**6501.79**	**3086.17**	**4**

*****